अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में 242 पैरामेडिकल पद खाली

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) झूठ और पाखंड की नींव पर खड़ी खट्टर सरकार आये दिन हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हल्ला करती आ रही है, उसका जीता-जागता उदाहरण अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है। छांयसा के मोठूका गांव स्थित उक्त मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी एवं डाक्टरों के 146 पद तो खाली हैं ही, साथ में पैरामेडिकल स्टाफ़ के भी 242 पद खाली हैं। जाहिर है कि जिस अस्पताल में न डॉक्टर होंगे और न ही पैरामेडिकल स्टाफ़ होगा वहां इलाज के लिये भला कौन मरने आयेगा?

पैरामेडिकल के उक्त खाली पदों को भरने के लिये विधिवत भर्ती के आवेदन मांगने की बजाय बीते सप्ताह सरकार ने नोटिस निकाला है कि राज्य के जिन-जिन अस्पतालों से जो कोई भी स्टाफ़ इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आना चाहे तो वह आवेदन कर सकता है। क्या गजब सोच है खट्टर सरकार की। भूखा-नंगा भिखारी दूसरे भूखे नंगे से उधार मांग रहा है। सर्वविदित है कि हरियाणा भर के किसी भी अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ़ पूरा नहीं है। लगभग हर जगह आधे से अधिक पद वर्षों से खाली पड़े हैं। उन्हें भरना तो दूर रहा, अब उन्हीं में से अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में बुलाये जा रहे हैं।

समझने वाली बात यह है कि कोई भी स्टाफ़, कहीं से भी अपनी जमी-जमाई जगह को छोड़ कर नई जगह पर क्यों आने लगा? हिसार, सिरसा, जींद, पंचकूला आदि दूर दराज के शहरों से उठ कर भला कौन यहां आना चाहेगा? लगभग हर कर्मचारी ने अपने-अपने स्थान पर कोई न कोई साइड कारोबार चला रखा होता है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा का भी मसला रहता है। इन सबके चलते केवल वही 20-30 लोग यहां आ सकते हैं जिन्हें अपनी पदोन्नत्ति नज़र आती होगी। कुल मिलाकर इन 242 पदों में से कम से कम 200 पद तो खाली रहने ही रहने हैं। इन हालात में खट्टर साहब का यह अस्पताल मरीजों का कैसा इलाज कर पायेगा समझना मुश्किल नहीं है।

लारे-लप्पे देने में माहिर भाजपा सरकार ने अब छेड़ा एफएनजी राग

मंझावली पुल : नौ साल, फिर भी अधूरा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बीते 8-9 साल की भाजपाई सरकार की कार्यशैली को देख कर बखूबी समझा जा सकता है कि केवल काम की बात करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं। काम की बात हर रोज करो और उसे गोदी मीडिया के माध्यम से जनता को हर रोज बताओ कि सरकार काम करने में जुटी हुई है। इसके विपरीत धरातल पर कुछ नहीं करना।

इसी कड़ी में एक नया शगूफ़ा एफएनजी यानी फ़रीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद मार्ग बनाने का पेश किया गया है। बीते छः महीने में इस शगूफे को कई बार मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पूरे जोर-शोर से प्रचारित किया जा रहा है। इस हवा-हवाई योजना में बताया जा रहा है कि ग्रेटर फ़रीदाबाद में स्थित अम्मा के अस्पताल से रिवाजपुर, शेरपुर खादर, लालपुर, किड़ावली गांव के पास से होते हुए सेक्टर-92 कन्हेड़ा कला तक जाएगी। यहां पर एक नया पुल यमुना नदी पर बना कर 90 मी. चौड़ी सड़क को जोड़ा जायेगा जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 157 से जाकर जुड़ेगी। इस सड़क के माध्यम से न केवल गाजियाबाद बल्कि यूपी के हर शहर को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रोजेक्ट को एक नया नाम एफएनजी दिया गया है।

इस परियोजना पर आने वाले खर्च का आधा हरियाणा व आधा यूपी सरकार द्वारा वहन करने की बात कही गई है। मजे की बात तो यह है कि किस दिन यह परियोजना शुरू होगी और किस दिन पूरी होगी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कभी किया जायेगा, किया भी गया तो वह बिल्कुल झूठा होगा जैसा कि मंझावली वाले यमुना पुल के बारे में हो रहा है।

संदर्भवश सुधी पाठक यह जान लें कि मंझावली यमुना पुल का शिलान्यास केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी व स्थानीय सांसद एवं मंत्री कृष्णपाल गूजर ने 15 अगस्त 2014 को किया था। उस वक्त यह कहा गया था कि दो साल में इस पुल को चालू कर दिया जायेगा। **'मज़दूर मोर्चा'** ने अनुभव के आधार पर उसी वक्त यह घोषित कर दिया था कि दो साल में पुल चालू करना तो दूर, इतने समय में ये डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ही बना लें तो बहुत बड़ी बात होगी। **'मज़दूर मोर्चा'** की बात आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। अभी तक भी पुल चालू नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में लगी मशीनरी 17 जनवरी 2023 को लिये गये चित्र में साफ़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पुल को जोड़ने के लिये सड़क का निर्माण अभी तक शुरू भी नहीं हो सका है जिसके बिना पुल बन भी जाये तो बेकार है।

चाहे एफएनजी निर्माण की घोषणा हो अथवा मंझावली पुल की, एक खास बात हमेशा पूरे जोर-शोर से कही जाती है कि इसके बन जाने से घंटों का सफ़र मिनटों में पूरा होगा।

लाभ गिनाते वक्त न केवल फ़रीदाबाद-नोएडा की दूरी घटने की बात की जाती है बल्कि गुड़गांव व जयपुर तक कि दूरी घटने का बखान किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि इससे हजारों-लाखों यात्रियों एवं वाहनों का समय व डीजल बचेगा, इससे लोगों को करोड़ों का लाभ होगा और प्रदूषण भी घटेगा। होने वाले इन सब सम्भावित फायदों का ज्ञान नेताओं के बताये बगैर भी जता को मालूम है। नेतागण तो इन्हें गिना कर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। इसी बात को उल्टा कर देखें तो उक्त फायदों के न मिलने से जनता को जो हानि हो रही है, उसकी दोषी तो भाजपाई सरकार बनती ही है।

भाजपा शासन में गायों की दशा निम्नत्तम स्तर पर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) गाय को माता कहने वाले इस भारतवर्ष में जितनी दुर्दशा गाय की होती रही है उतनी दुनियां के किसी भी देश में नहीं होती। जिस तरह से लावारिस गायों के झुंड के झुंड सड़कों, गलियों, बाजारों व खेतों में घूमते इस देश में मिलेंगे, अन्य किसी भी देश में नहीं मिल सकते। भूखी-प्यासी गाय जिस खेत में घुसती है वहीं उसे लट्ठ पड़ते हैं, जिस दुकान अथवा रेहड़ी पर मुंह मार कर कुछ खाने का प्रयास करती है वहीं उस पर लट्ठ पड़ते हैं। इसी के चलते किसी गाय का सींग टूटा है तो किसी की टांग तो किसी की आंख फूटी है। इन्हीं हालात के चलते ये भूखी गायें गंदगी के ढेरों पर गंद व पॉलीथीन खाती मिलेंगी।

भाजपा सरकार आने के बाद तो इनकी दुर्दशा और भी बढ गई है। अब न केवल इनके झुंडों की संख्या बढ गई है बल्कि सरकारी एवं गैर सरकारी गौशालाओं में भी कैद काट रही हैं। खट्टर ने हरियाणा की बागडोर सम्भालते ही गौ-सेवा आयोग बना कर उसका एक चेयरमैन बना दिया था। सर्वप्रथम पलवल के किसी भानीराम को तथा

चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग : गौ राजनीति के खिलाड़ी

अब श्रवण कुमार गर्ग को इस आयोग का चेयरमैन बनाया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य भर की 600 गौशालाओं में साढ़े 16 लाख से अधिक गायें कैद हैं। इन पर हरियाणा सरकार 50 करोड़ वार्षिक खर्च करने का दावा करती है। यह रकम इतनी गायों के लिये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इतनी रकम से तो उनके चारे व बीमारी का इलाज तो दूर पानी पिलाने का खर्च भी नहीं चल सकता।

गौशालाओं की हालत देखने वाले बताते हैं कि उनमें न तो गर्मी-सर्दी व बरसात से बचने के लिये शेड है और न ही अच्छी तरह टहल पाने की जगह क्योंकि कम स्थान में इतनी अधिक गायें घुसेड़ रखी हैं कि उनका खुल कर चलना-फिरना भी दूभर है। जहां तक बीमार गायों के इलाज का सवाल है, उस पर तो बात करना ही फिजूल है। यद्यपि संघी-भाजपाई रोगी गायों के इलाज एवं दवा-दारू का ढोल तो खूब पीटते हैं परन्तु धरातल पर निल बटा सन्नाटा है। जब पशु चिकित्सा सेवाओं के आभाव के चलते पालतू पशुओं का ही इलाज दुर्लभ है तो इन बेचारी लावारिस गायों को इलाज कहां सुलभ हो सकता है?

रही बात सरकार द्वारा 50 करोड़ खर्च करने की तो यह सही हो सकती है, परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस भ्रष्टाचारी युग में यह सारा पैसा बिना किसी सेंधमारी के गौमाताओं के मुंह तक पहुंच पाता हो। हां, गौमाताओं के सिर पर सवार होकर किसी न किसी संघी को गौ-आयोग के चेयरमैन बन कर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने का सुवअसर जरूर मिलता रहता है।